राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच

Forum for Awareness of National Security (FANS)
(Regd. No. S/1723/District South/2014)
101, H.I.G. DDA Flats, Block-1,
Motia Khan, Paharganj Pin Code. 110055.
M: 8178828297, 8375965010 Ph: 011-43524524

प्रस्ताव क्रम संख्या - 2

सीमायी इलाके में चीन का बढ़ता खतरा

भारत को चीन से निरंतर खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके कई आयाम हैं। लेकिन इसकी शुरुआत तिब्बत के हड़पने से शुरू होती है। भारत के द्वारा तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग की स्वीकृति से खतरा बढ़ गया। बाबासाहब अंबेडकर ने 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा था कि भारत एक मजबूत विदेश नीति में असफल रहा है। तिब्बत के चीन में मिलने से हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर होगी। जिसका अहसास हमें दशकों बाद होगा। डोकलाम साल 2017 में हुआ। बाबासाहब की बात कितनी सच निकली, तिब्बती के जाने से मुख्यत: दो तरह से भारत की सुरक्षा चीन के घेरे में आ गई। पहला भारत की सीमा तिब्बत से मिलती थी न कि चीन से।

भारत द्वारा आयोजित एशियाई सम्मेलन में भी तिब्बत का शिरकत एक आजाद देश के रूप में हुआ था। तिब्बत और नेपाल, भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट का काम करते थे, जो भारतीय सुरक्षा के लिए अहम था। तिब्बत के हड़पने के बाद चीन ने नेपाल की राजनीति और सामरिक समीकरण को बदलना शुरू किया। आज अगर नेपाल और भारत के बीच संबंधों में तल्खी है तो उसका कारण भी चीन है। पिछले कुछ दशकों से चीन नेपाल के उन सीमाई इलाके में मेंडेरियन भाषा के केंद्र चला रहा है, जिनकी सीमाएं भारत से मिलती हैं। भारत नेपाल सीमा आज भी खुला हुआ है। भाषा के नाम पर चीन द्वारा जासूसी और तमाम तरह के ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे भारत की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सके।

दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती पर्यावरण को लेकर उत्पन्न हो रही है। भारत की नदियां जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, तिब्बत की पहाड़ियों से निकलती हैं। चीन वहां पर डैम बनाकर नदियों के बहाव को बदल रहा है। आण्विक कचरे को भी उन मुहानों पर डालकर डंप कर रहा है, जिससे नदियां भी

विषाक्त हो रही हैं। जहां पर भी भारत की सीमा चीन से मिलती हैं, वहां से भारतीयों का पलायन हो रहा है, विशेषकर अरुणाचल और उत्तराखंड में यह स्थिति देखी जा सकती है। पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड में घोस्ट विलेज यानी निर्जन गांवों को फिर संवारने और पलायन थामने के राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। निर्जन गांवों को ही लें तो अब तक इनकी संख्या 1702 पहुंच चुकी है। उत्तराखंड की पलायन की भयावह तस्वीर को खुद ग्राम विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट तस्दीक करती है। यह बताती है कि प्रदेश के सभी जिले में पलायन का क्रम जारी है। लेकिन सर्वाधिक त्रस्त सीमावर्ती जिले हैं।

यही स्थिति अरुणाचल प्रदेश की भी है। 1046 किलोमीटर की सीमा अरुणाचल की चीन अधिकृत तिब्बत से मिलती है। इस पूरे इलाके में 600 के करीब गांव हैं, जिसकी आबादी महज 250 है। सारे लोग इटानगर और अन्य शहरों में पलायन कर गए। कारण चीन से उत्तपन्न संकट और सीमायी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। सीमायी इलाके में नागरिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। उत्तराखंड में करीब 1700 से ज्यादा गांव खंडहर बन चुके हैं। लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। कारण वहां भी बुनियादी सुविधाओं की कमी ही है।

<u>संकल्प प्रस्तावना :</u>

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच दृढ़ता से इस बात की पुष्टि करता है कि :

1. पलायन को रोकने के लिए सरकार को हरसंभव प्रयास करने होंगे। वहां के बाशिंदों के लिए बुनियादी सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध करवानी होगी। मसलन स्वास्थय, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार। सेवानिवृत्त सैनिकों को विशेष सुविधा प्रदानकर उन क्षेत्रों में बसाया जा सकता है। यह काम जितना जल्द किया जाएगा उतना ही देश के लिए बेहतर होगा।
2. भारत को अपने कूटनीतिक प्रयास के द्वारा विश्व बिरादरी के सहयोग से चीन पर लगातार दबाव बनाना होगा। और एक आजाद तिब्बत की मांग को मजबूती से रखने की जोर आजमाइश करनी होगी। कूटनीति के द्वारा दुनिया के सभी देशों के माध्यम से चीन पर दबाव बनाना होगा, जिससे एक स्वतंत्र तिब्बत की ईकाई को सुनिश्चित किया जा सके।
3. हमें अपनी सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को और मजबूत करना होगा, जिससे चीन की तल्खी को कम किया जा सके।